

बिहार विधान परिषद

(201वां मानसून सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

27 जून 2022

[कृषि - पथ निर्माण - ग्रामीण विकास - भवन निर्माण - ग्रामीण कार्य - पंचायती राज पशु एवं मत्स्य संसाधन].

Total Short Notice Question- 13

पशु अस्पताल का निर्माण

*1 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या पशु एवं मत्स्य संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा गांव में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय निजी भवन में विगत सैंतीस (37) वर्षों से कागज पर ही संचालित हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि संचालित हो रहे पशु चिकित्सालय का भवन बेहद जर्जर है तथा उसके पशु चिकित्सक कभी नहीं आते हैं जिसके कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर सरकारी जमीन या जमीन खरीदकर पशु अस्पताल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब

*2 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन किशनगंज जिले के अर्राबाड़ी में डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय संचालित है जिसमें स्वीकृत पद के अनुरूप शिक्षकों/वैज्ञानिकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के हित में शिक्षकों/वैज्ञानिकों की नियुक्ति-प्रक्रिया अविलंब शुरू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निर्माण कार्य प्रारंभ

*3 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या पथ निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य की दस मुख्य सड़कों पर आरओबी बन जाने से पांच घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से से पटना पहुंचा जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि इन सड़कों पर आरओबी बनाने हेतु वर्ष 2019 में ही रेलवे एवं पथ निर्माण विभाग के साथ करार होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का क्या औचित्य है, और सरकार कबतक आरओबी के निर्माण कार्य को पूरा करायेगी?

राशि देने पर विचार

*4 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या ग्रामीण विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना" के अंतर्गत आवास के साथ एक शौचालय दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चापाकल का प्रावधान नहीं है, जिस कारण लाभार्थी को पानी की घोर समस्या होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लाभार्थियों

की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में एक चापाकल के लिए भी अलग से राशि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गड्डे को भरकर समतल कराना

*5 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या पथ निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अशोक राज पथ पुरानी सिटी कोर्ट पटना से पटना सिटी चौक तक तीन महीने पूर्व गड्डा खोदा गया जो अबतक समतल नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अशोक राजपथ के अतिरिक्त अन्य सड़कों को खोदने के बाद मरम्मत नहीं की गयी है जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खोदे हुए गड्डे को भरकर समतल कराएगी, नहीं तो क्यों?

राशि उपलब्ध

*6 श्री दिनेश प्रसाद सिंह (मुज्जफरपुर स्थानीय प्राधिकार):

क्या पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के स्वीकृतादेश संख्या-58(स्वी.)/ पं.रा. दिनांक- 11.03.2022 द्वारा राज्य के सभी जिलों की जिला परिषदों/ पंचायत समितियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में षष्ठम वित्त की राशि का आवंटन दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है और इसके लिए दोषी कर्मी/पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को राशि उपलब्ध कराएगी, यदि हां तो कबतक?

आपूर्ति सहित कार्य

*7 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

क्या **भवन निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय सिविल कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सहित अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उपस्कर आदि टूटने के कारण कई अधिवक्ता एवं गवाह न्यायालय कक्ष में घायल होकर गिर गये है;

(ख) क्या यह सही है कि न्यायालय परिसर में लिफ्ट की खराबी की वजह से कई बार अधिवक्ताओं की जान किसी तरह से बचाई जा सकी है;

(ग) क्या यह सही है कि न्यायालय कक्ष का बरामदा और न्यायालय कक्ष अन्दर से भी बेमरम्मत रहने के कारण खतरनाक हो गए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा बेगूसराय न्यायालय परिसर, भवन, उपस्कर की अद्यतन स्थिति की जांच कराकर यथोचित कार्रवाई, नये उपस्कर आदि की आपूर्ति सहित कार्य कबतक करवाना चाहती है?

सड़क का निर्माण

*8 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या **पथ निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि एन.एच.- 83 पर पटना-गया-डोभी सड़क का निर्माण डेढ़ साल में आधा भी पूरा नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क में कुल 127 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था किन्तु अभी तक मात्र 52 किलोमीटर तक की सड़क बन पाई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र एवं तय समय सीमा में इस सड़क का निर्माण पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नई नीति बनाने

*9 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या **भवन निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में आठ करोड़ वर्ग फीट से अधिक में निर्मित सरकारी भवनों के रख-रखाव, मरम्मत एवं सुरक्षा हेतु एक नई नीति तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 2017 से प्रारंभ है;

(ख) क्या यह सही है कि पांच वर्षों के बाद भी नई नीति तैयार नहीं होने के कारण बहुत सा सरकारी भवन खंडहर होने की स्थिति में हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नई नीति बनाने का कार्य पूरा करेगी?

आरक्षण का शत प्रतिशत कार्यान्वयन

*10 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार पंचायती राज में अतिपिछड़े वर्गों के लिए सभी पदों पर 20% आरक्षण का प्रावधान है ;

(ख) क्या यह सही है कि पंचायती राज चुनाव 2022 के परिणाम के अनुसार अति पिछड़ा को जिला परिषद्, पंचायत समिति, मुखिया तथा वार्ड सदस्यों में 20% प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहेगी कि किन कारणों से आरक्षण का शत प्रतिशत कार्यान्वयन नहीं हुआ?

भुगतान हेतु आदेश

*11 श्री दिनेश प्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार):

क्या ग्रामीण विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला में मनरेगा योजना के अन्तर्गत हो रहे पक्के कार्यों की आवंटित राशि की 40% राशि के भुगतान की अनुमति जिला से लेनी पड़ती है और ऐसा बिहार के किसी और जिला में भी नियम लागू है या सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही भुगतान की स्वीकृति जिला से लेनी पड़ती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार

अन्य जिलों की भांति ही मुजफ्फरपुर जिला की ग्राम पंचायतों को अपने स्तर से भुगतान हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पुलों को शीघ्र बंद करने

***12 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **पथ निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में एन.एच. पर कई ऐसे पुल हैं, जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं और उन्हें बंद करने का आदेश सरकार द्वारा दे दिया गया है फिर भी वे चालू हैं;

(ख) क्या यह सही है कि छपरा जिला के सोनपुर-छपरा एन.एच. पर पट्टी पुल बिल्कुल जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और उस पर वाहनों का चलना खतरे से खाली नहीं है फिर भी वह चालू है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पट्टी पुल सहित राज्य के एन.एच. पर स्थित सभी जर्जर पुलों को शीघ्र बंद करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

यातायात व्यवस्था

***13 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **पथ निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय में किसी भी पथ से प्रवेश के समय लगभग हर तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण शहर की आंतरिक यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित भागलपुर शहर में यातायात की सुगमता हेतु पटना की तर्ज पर ही 'गंगा एक्सप्रेस वे' के निर्माण का विचार रखती है ताकि शहर की पूर्ण यातायात व्यवस्था का समायोजन सुनिश्चित तरीके से संभव हो, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?
